

प्रेषक,

संख्या-889/XIV-4/2017-5(18)/2010

आनन्द स्वरूप,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियां,

उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 2, जुलाई, 2017

विषय-पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों हेतु उर्वरक परिवहन पर राज सहायता मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-1147/नियोजन-उर्वरक/2017-18, दिनांक 23 मई, 2017 एवं संख्या-2638/नियोजन-उर्वरक/2017-18, दिनांक 11 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक आपूर्ति के लिए रेल हैड से सहकारी समिति के गोदामों/बिक्री केन्द्रों तक परिवहन-व्यय पर राज सहायता मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि में से ₹40,00,000.00 (चार लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संस्था/समितियों द्वारा ₹1000 प्रतिटन परिवहन व्यय वहन किया जायेगा, जिसकी समग्र सूचना वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। उक्त धनराशि की जनपदवार फॉट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाय।

- (3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपदों में जनपद-वार लक्ष्य के सापेक्ष विवरित उर्वरक की मात्रा, मैदानी जनपदों के सापेक्ष पर्वतीय जनपदों में वितरित उर्वरक की मात्रा लक्ष्य के अनुसार हो।

(2)

तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य समयबद्ध आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) धनराशि का योजनावार मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह या ठीक अगले माह की 5 तारीख तक नियमित रूप से बी0एम0-8 प्रपत्र पर वित्त विभाग/प्रशा0विभाग तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(8) उक्त व्यय शासन के वर्तमान में लागू सुसंगत आदेशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। व्यय करते समय भित्तव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी आदेशों एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-00-106 बहुददेशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता-02-उर्वरक परिवहन पर राज सहायता के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता के नामे जला जायेगा।

3- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र सख्या-312/3(50)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं सख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

सलगनक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आनन्द स्वरूप)

अपर सचिव।

सख्या-889(1)/XIV-1/2017, तद्विनाशित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, औद्योगिक बिल्डिंग मान्यता क्षेत्र, उत्तराखण्ड।